

रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2019

दिनांक : 07.03.2019

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2019

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

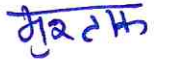
(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : Dispensation of conditions of applying for Government Accomodation and furnishing of 'No Accomodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 5 मार्च, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं० 2/5/2017ई-II(बी), जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 2/5/2017-E.II (B) dated 5th March, 2019 on the above subject, which is available on the website of MoF(DoE), is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

संलग्नक: यथोपरि



(मुश्ताक अहमद)

रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4 (स्थानीय)।
2. प्रशासन-12 (स्थानीय)। : उक्त ज्ञापन के पैरा 3 के सम्बंध में सूचनार्थ।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्वायर, दिल्ली छावनी।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

-२०-

(विजय रैना)

व० लेखा अधिकारी(प्रशा)

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Dispensation of conditions of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance.

Several references are being received in this Department to review the condition of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' for admissibility of House Rent Allowance as contained in Para 4(a) of this Department's O.M. No. 2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 read with Para 1(1) of O.M. No.11011/1/E.II(B)/75 dated 25.02.1977.

2. The matter has been examined in this Department and in supersession of Para 4(a) of this Department's O.M. No. 2(37)-E.II(B)/64 dated 27.11.1965 read with Para 1(1) of O.M. No.11011/1/E.II(B)/75 dated 25.02.1977 and to simplify the procedure relating to grant of House Rent Allowance to Central Government employees, the President, in consultation with Ministry of Housing and Urban Affairs and the Staff Side of the National Council (J.C.M.), is pleased to decide that the conditions of applying for Government Accommodation and furnishing of 'No Accommodation Certificate' by Central Government employees to become eligible for House Rent Allowance, are dispensed with for all places, in respect of General Pool Residential Accommodation(GPRA) controlled by Directorate of Estates.

3. Ministries/Departments having their separate pool of residential accommodation for their employees other than GPRA, may adopt these provisions, wherever feasible.

4. These orders shall be effective from the date of issue of the orders.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

Hindi version is attached.



(Nirmala Dev)

Deputy Secretary to the Government of India

To,

All Ministries and Departments of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to C&AG and UPSC etc. (with usual number of spare copies) as per standard endorsement list.

सं.2/5/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

5 मार्च, 2019

कार्यालय जापन

विषय: मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में छूट।

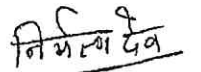
इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.जा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.जा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) में यथा निहित मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों की समीक्षा के लिए इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

2. इस मामले पर विभाग में विचार किया गया है और इस विभाग के दिनांक 25.02.1977 के का.जा.सं. 11011/1/ई.II(बी)/75 के पैरा 1(1) के साथ पठित दिनांक 27.11.1965 के का.जा.सं. 2(37)-ई.II(बी)/64 के पैरा 4(क) का अधिक्रमण करते हुए और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिए जाने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ पक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का पात्र बनने के लिए सरकारी आवास के लिए आवेदन करने और 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करने की शर्तों में सभी स्थानों के लिए छूट दी जाती है।

3. ऐसे मंत्रालय/विभाग, जिनके पास अपने कर्मचारियों के लिए जीपीआरए के अलावा पृथक आवास पूल हैं, जहां भी संभव हो, इन प्रावधानों को अपना सकते हैं।

4. ये आदेश इनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।



(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रति, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।